[श्री जनेश्वर मिश्र]

उसी तरह से जिस तरह से टाडा के बारे में प्रधानमंत्री जी ने जो इस सदन में कहा उसके दूसरे ही दिन गृह मंत्री जी ने कुछ इस तरह का संदेश दिया कि यह उससे उल्टे किस्म का कदम है । अगर प्रधानमंत्री के उस भाषण को, जो उन्होंने लाल किले पर झंडा फहराते समय दि था, उसको भी झुटला दें या उसको डिस्प्यूट में ला दे तो स पर मुझे खेद एतराज है । अगर माननीय सदस्य प्रधानमंत्री के वक्तव्य को मानते हैं और दूसरे दिन गृह मंत्री का दूसरे किस्म का वक्तव्य आ जाए तो यह बड़ा शोभनीय काम हो जाएगा, इस देश के जनतंत्र के लिए, यह ऐतराज मैं नोट कराना चाहता हूं ।

उपसभापति : इस बारे में तो हाउस में यूनेनिमस रेजोल्यूशन पास हुआ है । दोनों हाउस में ऐसा रेजोल्यूशन पास है ।

श्री जनेश्वर मिश्र : इन्होंने जो कहा है, उस पर मैं कह रहा हूं ।

उपसभापति : इसमें कोई दो राय नहीं है कि कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसको पी.ओ.के. कहते हैं, पाकिस्तान आक्युपाइड कश्मीर

श्री जनेश्वर मिश्र : इन्होंने जो कहा है उस पर मैंने अपना ऐतराज नोट कराया है ।

उपसभापति : मैं तो हमेशा कहती हूं कि इसको खाली कराना है ।

The House then adjourned for lunch at thirty-five minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty-seven minutes past two of the clock,

The Vice-Chairman (Shri Suresh Pachouri) in the Chair.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): We will now take up the Zero Hour submissions.

RH. NON-UTILISATION OF RS. 394 CROSS ALLOTTED FOR D.E.S.U.

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Vice-Chaiman, Sir, I would like to raise an issue relating to Delhi. It is a matter of concern that in Delhi, people who are living, not in the areas where the Members of Parliament are living, but in the urban and semi-urban areas, and espscially in the rural areas, are experiencing power cuts everyday. But, unfortunately, the BJP Government which rules the Capital Territory of

Delhi and which was allotted Rs. 394 crores by the Government of India for the purpose of making improvements in DESU, failed to utilise this amount and the funds have been surrendered It shows the inefficiency and also the lack of experience on the part of the Government in not being able to utilise the funds for the purpose for which these were given. Sir, it was not in the year, 1994-95 alone, but we know pretty well that even in the year, 1993-94, an amount of Rs. 40 crores remained unutilised and the funds lapsed.

I would like to mention that there are six projects; here—Pappankalan I & II, Shastri Park, (Nangloi Water Treatment Plant, Wazirabad Water Treatment Plant and Rohini Extension—I. These are the areas where power stations have to be set up for purposes of power generation and transmission by the State Government of Delhi. But, unfortunately, the Chief Minister is busy in trying

to handle the political activities of the BJP alone and is not tackling the problems of the people of Delhi as far as electichy and water supply are concerned. Sir, I am not making any remark, but this is a remark which has been made by a BJP MLA. Sir, the Chief Minister called a meeting of the officials, had discussions with them and told them to proceed with the project works. Sir, I would like to quote the remark which has been made by the BJP MLA, He says, "It seems that the DESU officials don't carry out the CM's orders." This is the observation made by the BJp MLA himself.

Sir, I would like to further add that two committees had been appointed for power generation and also for the purpose of transmission of power without affecting the people of Delhi. One was the Advani Committee. That Commitee submitted its report in June, 1994, but no action was taken by the Delhi Government on that. Sir, there was another committee, namely, Vasant Committee. The report of that Committee is also lying on the table of the Chief Minister and no action was taken. Sir, every day, the people of Delhi are feeling the pinch of power failure, especially the people who are living in rural areas and also in the semi-urban areas. It is a very important thing. It is quite unfotunate that the State Government is not willing to spend and has no efficiency to spend Rs.394 crores that have been allocated for the DESU. Sir, day in day out, delegations of Members of Parliament and also the MLAs of Delhi and the Chief Minister go to the Home Minister whose Ministry is the nodal Ministry and demand more funds for Delhi. They go to the Home Minister for getting more fund for Delhi. In fact, I supported that when I spoke on the Bill. I supported the move for more allocations far sanitation, electricity, water supply etc., for Delhi. But unfortunately, when the funds nave been given, the Chief Minister and the Council of Ministers are not able to spend the funds in a proper manner, though the funds have been made available to them. Therefore, Sir, it is high timee that the Government of India intervened and saw to it that the funds were properly spent by the State Government cf Delhi.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): Shri Satya Prakash Malaviya.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे समय दिया....

SHRl VIREN J. SHAH (Maharashtra): Vice-Chairman, Sir, Mr. Kohli wants to say something on that. ... *(Interruptions)* ...

श्री ओ०पी० कोहली (दिल्ली) : मैं सिर्फ एक मिनट लूगा। यह बात ठीक है कि दिल्ली में जगह जगह...

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: He should speak only after me. ... *(Interruptions)..,*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): He is speaking on the matter raised by Mr. V. Narayanasamy.

श्री ओ० पी० कोहली : वाइस चेयरमैन साहब, यह बात ठीक है कि बिजली की जगह जगह कटौती के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। यह बात भी सच है कि दिल्ली सरकार ने इस व्यवस्था में सुधार करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। जो दिक्कत की बात है वह यह है कि दिल्ली की सरकार की एक बहुत

जायज शिकायत है कि केन्द्र की ओर से उसको सहयोग नहीं मिल रहा है । केन्द्र का रवैया ठीक तरीके से दिल्ली की सरकार को चलाने के मामले में जो सहयोगात्मक होना चाहिए, वैसा सहयोगात्मक न होकर असहयोगात्मक और नकारात्मक है ।

बाइस चेयरमैन साहब, इसलिए मूल सवाल यह है कि बिजली की जगह जगह परेशानी की जो माननीय सदस्य ने चिंता व्यक्त की है मैं उसकी चिंता को तो शेयर करता हूं लेकिन बुनियादी बात इसमें यह है कि दिल्ली की सरकार और केन्द्र सरकार के बीच में किस प्रकार का रिश्ता होना चाहिए । दिल्ली की सरकार को जो अधिकार मिले हुए हैं वे लोगों की आकांक्षाओं को ठीक तरीके से नहीं रखते । डेसू में जो घाटा चला आया है वह इस सरकार के दौरान पैदा नहीं हुआ है । डेसू का घाटा एक्युमुलेटेड घाटा है, उस एक्युमुलटिड घाटे के लिए आप जिम्मेदार हैं । जो बात नारायणसामी जी ने उठाई है उस बात को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए । डेसू की इनइफीशियंसी, अकुशलता डेसू में फैला हुआ भ्रष्टाचार, बड़े पैमाने पर बिजली की चोरी, फिर दिल्ली में बी०जे० पी. की सरकार के आने के बाद पैदा हुई चीजें नहीं हैं । ये उसको विरासत में मिली हैं । उसके लिए अगर कोई जिम्मेदारी है तो वह पार्टी जिम्मेदार है जिसकी सरकार पहले दिल्ली में भी थी और केन्द्र में भी थी, यह बात मैं रेखांकित करना चाहता हूं ।

SHRl V. NARAYANASAMY: Now that there is an elected Government with elected Chief Minister, DESU is under their control ... *(Interruptions)*. ..

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): Mr. Shah, I allowed Mr. Kohli even though his name was not there. *(Interruptions)*

SHRI VIREN J. SHAH; Whatever you say, we always accept ..... *(Interruptions),*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): I am not allowing the discussion. ... *(Interruptions)* ...

SHRI V. NARAYANASAMY: Now, the DESU is under their control. Efficiency is to be maintained by them. It is their job. They cannot blame the Centre. When the funds are providing the State Government is not spending the funds. They have surrendered the funds. So, it is the inefficiecy of the State Government.

RE HOMAGE TO FREEDOM FIGHTERS OF FIRST WAR OF INDEPENDENCE, 1857

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) : मान्यवर, आज 10 मई का ऐतिहासिक दिन है और आज का दिन राष्ट्रवासियों को यह याद दिलाता है कि आज ही के दिन मेरठ, उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता के प्रथम भारतीय संग्राम की शुरूआत हुई थी । 1857 की एतिहासिक जनक्रांति के प्रथम शहीद स्व. मंगल पांड थे । उन्हें तो 8 अप्रैल को ही बारकपुर छावनी में फांसी दे दी गई थी और इस प्रकार से स्वाधीनता संग्राम के प्रथम शहीद हो गए । दो दिन बाद जमादार ईश्वर पांडे को भी फांसी की सजा सुना दी गई क्योंकि उन्होंने मंगल पांडे की गिरफ्तारी का हुक्म नहीं दिया था और न मंगल पांडे को गिरफ्तार करने में अंग्रजों की सहायता की थी । उन्हें भी 21 अप्रैल को बारकपुर में ही फांसी दे दी गई । मान्यवर, जिन लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया उन पर बकायदा मुकदमा चलता था । उसके बाद उनको अंडेमान निकोबार भेज दिया जाता था इस सिलसिले में इलाहाबाद के एक मौलवी लियाकत अली थे जिनके सिलसिले में 24 जुलाई 1872 को वहां के सैशन जज ए. आर. पोलोक जिन्होंने कि आजीवन कारावास की सजा